नईदुनिया

खरीफ फसलों पर संकट : महाराष्ट्र और तेलंगाना में 85 फीसदी तक घटी बुवाई ; कमजोर मानसून से झटका

नई दिल्ली

मानसून की सुस्ती ने इस साल देश के बड़े कृषि उत्पादक राज्यों को चिंता में डाल दिया है। इन राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाईपिछले साल के मुकाबले 85 फीसदी तक कम हुईहै। महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार तक महाराष्ट्र में सिर्फ 5,16,250 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई हो सकी है, जो पिछले साल के 33.8 लाख हेक्टेयर से करीब 85 फीसदी कम है। राज्य के सामान्य खरीफ क्षेत्र (157.5 लाख हेक्टेयर) का अभी तक सिर्फ 3 फीसदी हिस्सा ही कवर हो पाया है। महाराष्ट्र में बारिश तो शुरू हो गई है, लेकिन कमी अभी तक पूरी नहीं हुई है। राज्य में एक से 24 जून के दौरान सामान्य से 63 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। जलाशयों में पानी का स्तर घटकर 23 फीसदी रह गया है, जो पिछले साल 40 फीसदी था। राज्य में धान का रकबा 58,583 हेक्टेयर से घटकर 29,525 हेक्टेयर, मक्का 3.66 लाख हेक्टेयर से गिरकर 30,428 हेक्टेयर और बाजरा 1.08 लाख हेक्टेयर से घटकर 2,743 हेक्टेयर रह गया है। सोयाबीन का रकबा 11.5 लाख हेक्टेयर से घटकर सिर्फ 60,441 हेक्टेयर पर आ गया है। कपास की बुवाई भी 11.5 लाख हेक्टेयर से घटकर 3,40,817 हेक्टेयर रह गई है। वहीं, तेलंगाना में 14.8 लाख एकड़ में बुवाई हुई है, जो पिछले साल के 28.4 लाख एकड़ से 48 फीसदी कम है। यह सामान्य सीजन क्षेत्र 132.4 लाख एकड़ का 11 फीसदी ही है। प्रदेश में जून में अब तक 84.6 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 17 फीसदी कम है। हालांकि, जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल से बेहतर है।

ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री में आ सकती है गिरावट – ट्रैक्टर और एंट्री-लेवल दोपहिया बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में बिक्री मजबूत रही थी, लेकिन खेती की इस सुस्ती के कारण साल का अंत मामूली बढ़त या गिरावट के साथ हो सकता है। ग्रामीण मांग कमजोर होने के कारण प्रीमियम पर्सनल केयर, पैकेज्ड स्नैक्स, गर्म पेय पदार्थ और होम इंप्रूवमेंट से जुड़े सामानों की बिक्री पर बड़ी मार पड़ सकती है। हालांकि, खाद्य और जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ने का अनुमान है।

राजस्थान में 20% हिस्सा कवर – राजस्थान में सोमवार तक 32.78 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल के 32.84 लाख हेक्टेयर के लगभग बराबर है। राज्य के सामान्य क्षेत्र 164.1 लाख हेक्टेयर का 20 फीसद हिस्सा कवर हो चुका है।

न्यूज ब्रीफ

एआई से उपजे साइबर खतरों से निपटने सरकार बनाएगी एकीकृत कमांड सेंटर

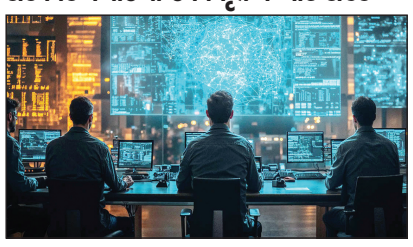

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और एंथ्रोपिक के क्लाड मिथोस जैसे माडलों से उत्पन्न साइबर सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार एक सशक्त और एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि यह कदम एआई से जुड़े नए खतरों के प्रति देश की नीतिगत प्रतिक्रिया को मजबूत करेगा। यह नई संस्था इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करेगी। इसका मुख्य कार्य एआई खतरों पर नीतिगत प्रतिक्रिया और केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। अधिकारियों के अनुसार, सरकार को एकीकृत कमांड सेंटर की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि फ्रंटियर एआई से उत्पन्न खतरों पर प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम होगा और जोखिम तेजी से बढ़ेंगे। सरकार का मानना है कि इन नए माडलों से निपटने के लिए एक एकीकृत नीति प्रतिक्रिया आवश्यक है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नए संगठन में सरकार, शिक्षाविद और नई एआई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आईटी मंत्रालय के नए एआई कानून से इस केंद्र को अधिकार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, सरकार उन कुछ कंपनियों से भी संपर्क कर रही है जिनके पास क्लाड सुरक्षा पहुंच है, ताकि वे अपने नतीजों को उद्योग के साथ साझा करें।

अप्रिलिया ने लांच किए नए ट्रिब्यूट एडिशन माडल

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में अप्रिलिया कंपनी ने 2 स्पोर्टी स्कूटरों, एसआर 125 और एसआर 175 के नए ट्रिब्यूट एडिशन माडल लान्च कर दिए हैं। दिल्ली में इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.17 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि रंग और डिजाइन में बदलाव के अलावा इन स्कूटर्स के यांत्रिक फीचर्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।इन खास स्कूटर्स को कैमलाज लिवरी के साथ पेश किया गया है, जो उन्हें एक विशिष्ट और आकर्षक रूप प्रदान करता है। डिजाइन की बात करें तो, दोनों ही माडलों को मैट-फिनिश के साथ गहरे मिलिट्री ग्रीन बेस रंग में रंगा गया है, जिससे उनका स्पोर्टी अपील और भी निखर कर आता है। स्कूटर के फ्रंट एप्रन और साइड प्रोफाइल पर पीले और नारंगी रंग की आकर्षक पट्टियां दी गई हैं, जो उनकी पहचान को और मजबूत करती हैं। इसके अतिरिक्त, इनके 14-इंच के पहियों पर लाल रंग की पट्टी की निरंतरता बरकरार रखी गई है, जो समग्र डिजाइन में एक डायनामिक टच जोड़ती है। डिजाइन और रंगों का यह संयोजन एसआर 175 और एसआर 125 दोनों में समान है, जिससे एक एकजुट ट्रिब्यूट थीम मिलती है। पावरट्रेन की बात करें तो, अप्रिलिया एसआर 125 में 124 सीसी का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 10.6 हार्सपावर की शक्ति और 10.4 न्यूटन मीटर का टार्क उत्पन्न करता है। वहीं, बड़े माडल अप्रिलिया एसआर 175 में 174 सीसी का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 13.2 हार्सपावर की अधिक शक्ति और 14.1 न्यूटन मीटर का टार्क प्रदान करता है।

एमेजान का भारत में 13 अरब डालर का नया निवेश, कुल नियोजित निवेश 48 अरब डालर पहुंचा

नई दिल्ली। वैश्विक ई-कामर्स दिग्गज एमेजान ने भारत में अपने निवेश को और गति देने का ऐलान किया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद 13 अरब डालर (लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक) के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की। इस नई घोषणा के साथ, वर्ष 2030 तक भारत में एमेजान का कुल नियोजित निवेश लगभग 48 अरब डालर हो जाएगा। एंडी जेसी इस समय भारत दौरे पर हैं और उन्होंने राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद इस बड़े निवेश का ऐलान किया। कंपनी ने छह महीने पहले 2030 तक भारत में अपने सभी कारोबारों में 35 अरब डालर के निवेश की घोषणा की थी, जिसमें अब यह अतिरिक्त 13 अरब डालर शामिल हो गए हैं। कुल 48 अरब डालर के इस निवेश में से, कंपनी लगभग 21 अरब डालर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्लाउड अवसंरचना के विस्तार पर खर्च करेगी।

आटो सेक्टर में बंपर बिक्री की उम्मीद, जून में दिखेगी रौनक

कारों की डिमांड ज्यादा, 20 फीसदी से अधिक ग्रोथ के आसार

आसान लोन और नए माडल्स ने बढ़ाया उत्साह

टाटा मोटर्स और महिंद्रा में सबसे बड़ी बढ़त की उम्मीद

नई दिल्ली

जून महीना भारतीय आटो उद्योग के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। एक ब्रोकरेज की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, नई गाड़ियों की मजबूत मांग, ग्राहकों के लिए आसान वाहन ऋण और निर्यात में उल्लेखनीय सुधार के चलते जून में वाहन कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यात्री वाहन, दोपहिया, कमर्शियल वाहन और ट्रैक्टर, सभी प्रमुख श्रेणियों में बिक्री में वृद्धि का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जून में कारों की बिक्री 20 फीसदी से अधिक बढ़ सकती है।

लोगों के लिए वाहन खरीदना पहले से आसान हुआ है, बाजार में नए माडलों की उपलब्धता बढ़ी है और आसान फाइनेंस विकल्प इसकी प्रमुख वजह होंगे। टाटा मोटर्स की कारों की बिक्री में करीब 55 फीसदी, महिंद्रा में 24 फीसदी, मारुति सुजुकी में 10 फीसदी और हुंडई की बिक्री में लगभग 1 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है। दोपहिया वाहन: दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। शादी-ब्याह का सीजन, सुलभ लोन और अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी बाजारों में बढ़ता निर्यात इस श्रेणी को रफ्तार देगा। नुवामा का अनुमान है कि टीवीएस मोटर की बिक्री में लगभग 29 फीसदी, रायल एनफील्ड की 28 फीसदी और बजाज आटो की 22 फीसदी की वृद्धि संभावित है। हालांकि, हीरो मोटोकार्प की बिक्री पिछले साल के उच्च आधार के कारण करीब 2 फीसदी घट सकती है। ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन भी रहेंगे मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, किसानों के पास बढ़ती नकदी और आसान ऋण उपलब्धता के चलते ट्रैक्टरों की बिक्री में भी 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि, डीजल की बढ़ती कीमतें किसानों की लागत बढ़ा सकती हैं। वहीं, कमर्शियल वाहन (ट्रक और बस) सेगमेंट भी मजबूत प्रदर्शन करेगा, जिसमें टाटा मोटर्स अपने नए और कम खर्च वाले माडलों के दम पर सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ज्यादातर वाहन कंपनियों के निर्यात में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे कुल बिक्री आंकड़ों को और मजबूती मिलेगी।

हुंडई की दो सालों में पांच नई गाड़ियां लान्च करने की योजना

नई दिल्ली । वाहन निर्माता कंपनी हुंडई भारतीय बाजार में अपनी दूसरी पोजीशन को बनाए रखने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। कंपनी अगले दो सालों में पांच नई गाड़ियां लान्च करने की योजना बना रही है, जिनमें नई क्रेटा से लेकर 7-सीटर एसयूवी तक शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले अगली पीढ़ी की क्रेटा एसयूवी है, जिसकी टेस्टिंग भारत और दक्षिण कोरिया में चल रही है। यह नए के3 प्लेटफार्म पर आधारित होगी और इसमें पूरी तरह से नया डिजाइन, बड़ी टचस्क्रीन और एक मजबूत हाइब्रिड वर्जन मिलने की उम्मीद है, जो 2027 की शुरुआत में आ सकती है। इसके बाद हुंडई बेयोन क्रासओवर एसयूवी आएगी, जिसे वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया जाएगा। यह आधुनिक डिजाइन, डुअल 12.3-इंच स्क्रीन और स्ट्रान्ग-हाइब्रिड इंजन के साथ 2026 के अंत तक लान्च हो सकती है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, हुंडई एचई1आई (॥श्व1ढ्ढ) इलेक्ट्रिक माइक्रो-एसयूवी लाने वाली है, जो टाटा पंच ईवी को टक्कर देगी। यह डेडिकेटेड ई-जीएमपी प्लेटफार्म पर बनेगी और 300 से 350 किमी की रेंज देने का दावा करेगी, जिसके 2026 में आने की संभावना है। कंपनी अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक, चौथी पीढ़ी की आई20 को भी पेश करेगी, जिसमें नया तेज डिजाइन, डुअल 12.3-इंच स्क्रीन और बेहतर सुरक्षा मिलेगी, जो 2027 में आ सकती है।

कोडियाक आरएस की बुकिंग शुरू

नई दिल्ली

गुणवत्तायुक्त कार निर्माता कंपनी स्कोडा ने अपनी उच्च-प्रदर्शन वाली एसयूवी, कोडियाक आरएस की बुकिंग शुरू कर दी है। अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग 55 से 60 लाख रुपये के बीच हो सकती है। तीन लाख रुपये की आरंभिक बुकिंग राशि के साथ, यह वाहन भारत में केवल 50 इकाइयों की सीमित संख्या में उपलब्ध होगा, जो इसे विशेष ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है।

यह पहली बार है जब स्कोडा भारत में आक्टाविया आरएस के अलावा किसी अन्य आरएस माडल को आधिकारिक तौर पर पेश कर रही है, जिससे वाहन प्रेमियों में काफी उत्साह है।

नई कोडियाक आरएस में वही दमदार दो लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो आक्टाविया आरएस में भी मिलता है, लेकिन यहां इसे 265 अश्वशक्ति और 400 न्यूटन मीटर टार्क के साथ अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यह इंजन सात-गति वाले स्वचालित द्वि-क्लच गियरबाक्स और आल-व्हील-ड्राइव प्रणाली से लैस है, जो इसे शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 6.3 सेकंड में प्राप्त करने में मदद करता है। इसकी अधिकतम गति 231 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसके खेल-उन्मुख प्रदर्शन को उजागर करती है। वाहन में उन्नत अनुकूली सस्पेंशन प्रणाली दी गई है, जिसे चालक 15 स्तरों तक समायोजित कर सकता है, साथ ही इसमें ईको, स्पोर्ट और स्नो जैसे विभिन्न ड्राइविंग मोड भी उपलब्ध हैं।

बाहरी डिजाइन को सामान्य कोडियाक से अधिक आक्रामक बनाया गया है, जिसमें नए बंपर, चमकदार काले सजावटी तत्व, आरएस प्रतीक चिन्ह और 20 इंच के मिश्रधातु पहिए शामिल हैं। केबिन में काले रंग की थीम के साथ लाल सिलाई, आरएस स्टीयरिंग व्हील और आरामदायक स्पोर्ट सीटें मिलती हैं, जो सात सीटों के साथ प्रीमियम और स्पोर्टी अनुभव प्रदान करती हैं। सुविधाओं में लगभग 13 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल चालक डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, तीन-क्षेत्रीय तापमान नियंत्रण, और वेंटिलेशन व मसाज वाली इलेक्ट्रिक सीटें शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें नौ एयरबैग और उन्नत चालक सहायता प्रणालियां (एडीएएस) भी मौजूद हैं।

ईवी कारें हो सकती है महंगी, रीसाइक्लिंग नियमों पर सायम ने जताई चिंता

नई दिल्ली। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम (सायम) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को आगाह किया है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित बैटरी रीसाइक्लिंग लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतों में 3 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। संगठन का मानना है कि इन सख्त नियमों से देश में ईवी की बिक्री पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सायम ने पिछले साल नवंबर में सीपीसीबी को भेजे पत्र और हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक में अपनी चिंताएं रखीं। उनका कहना है कि मौजूदा नियमों को मानने से औसतन 35-40 किलोवाट घंटे वाली इलेक्ट्रिक कार बैटरी की लागत में 8,000 से 25,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है, जिसमें बैटरी संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग का खर्च अलग से होगा। सायम का मुख्य तर्क यह है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत वाहन विनिर्माताओं को 8 साल के उपयोग के बाद 70 फीसदी बैटरियां (जो अंतत: 82 फीसदी तक बढ़ेंगी) एकत्र करनी होंगी। जबकि लीथियम आयरन फास्फेट (एलएफपी) बैटरियों की उम्र काफी लंबी होती है।

मुंबई पोर्ट का 3500 करोड़ से अधिक का मेगा प्लान क्षमता विस्तार और राजस्व विविधीकरण पर जोर

नई दिल्ली

मुंबई पोर्ट प्राधिकरण (एमबीपीए) ने अपने 154वें स्थापना दिवस पर 3,541 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का अनावरण किया है। इन पहलों का लक्ष्य कार्गो-हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना, गैर-पोर्ट राजस्व धाराओं को मजबूत करना और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी उपस्थित थे।

एमबीपीए की इन परियोजनाओं में बर्थ का आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी अपग्रेडेशन, एक मरीना का विकास और वाटरफ्रंट सौंदर्यीकरण शामिल हैं। घोषित 3,541.29 करोड़ रुपये के निवेश के अतिरिक्त, 132.29 करोड़ रुपये की सात परियोजनाएं उद्घाटन के लिए तैयार हैं, जबकि 1,354.59 करोड़ रुपये की 34 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। प्रमुख पहलों में इंदिरा डाक पर बर्थ का आधुनिकीकरण, कार्गो भंडारण सुविधाओं का विस्तार, क्रूड आयल बर्थ की क्षमता वृद्धि, रूफटाप सोलर पैनल की स्थापना और डिजिटलीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

बंदरगाह ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई मरीना और एक वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट

विकसित करने की भी योजना बनाई है। अपनी संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति के तहत, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण ने इंदिरा डाक पर बर्थ क्लस्टर्स के संचालन और रखरखाव के लिए समझौते भी किए।

पहले क्लस्टर (10 बर्थ) को जे एम बक्शी पोर्ट्स ऐंड लाजिस्टिक्स को 10 वर्षों के लिए 770 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ आवंटित किया गया है, जबकि दूसरे क्लस्टर (11 बर्थ) को एम डिनशा ऐंड कंपनी को 217 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ दिया गया है। एमबीपीए अध्यक्ष डा. एम अंगमुथु ने मुंबई पोर्ट को व्यापक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के रूप रूप में विकसित करने पर जोर दिया।

रियल एस्टेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, शीर्ष पदों तक पहुंच पर अब भी चुनौती

नई दिल्ली

रियल एस्टेट क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। अब महिलाएं केवल घर खरीदने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डेवलपर, आर्किटेक्ट, उद्यमी और प्रापटेक विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी पहचान बना रही हैं। इसके बावजूद फैसले लेने वाले शीर्ष पदों और नेतृत्व की भूमिकाओं में उनकी भागीदारी सीमित है।

एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में केवल 1 से 2 फीसदी महिलाएं ही नेतृत्व पदों तक हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी में

महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 48.5 फीसदी है, लेकिन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत 7.1 करोड़ लोगों में उनकी भागीदारी केवल 10 फीसदी के आसपास है।

हालांकि रियल एस्टेट से जुड़े कई पेशों में शुरुआती स्तर पर महिलाओं की भागीदारी 40 से 45 फीसदी तक पहुंच चुकी है, लेकिन करियर के मध्य चरण में बड़ी संख्या में महिलाएं कई कारणों से क्षेत्र छोड़ देती हैं। इसका सीधा असर वरिष्ठ प्रबंधन और नेतृत्व पदों पर उनकी संख्या में दिखाई देता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं की ज्यादा भागीदारी केवल समानता का मुद्दा नहीं है, बल्कि उद्योग के सतत विकास और देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी जरुरी है। नारेडको माही की अध्यक्ष स्मिता पाटिल का कहना है कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है।

वहीं जेएलएल इंडिया में गवर्नमेंट एडवाइजरी और इंफ्रास्ट्रक्चर साल्यूशंस के प्रमुख ए शंकर के मुताबिक रियल एस्टेट क्षेत्र में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के नेतृत्व पदों तक पहुंचने में कई बाधाएं मौजूद हैं। इनमें वेतन असमानता सबसे बड़ी चुनौती है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 30 से 40 फीसदी तक कम वेतन मिलता है। निर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की औसत दैनिक आय 412 रुपए बताई गई है, जबकि पुरुष श्रमिकों की आय इससे काफी ज्यादा है। इसके अलावा सीमित पदोन्नति अवसर, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, बच्चों की देखभाल की सुविधाओं की कमी और कार्यस्थल से जुड़ी चुनौतियां भी महिलाओं की प्रगति में बाधक बनती हैं।